SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I appreciate the appeal made by Yashwantji. But Sir, as the Chairman, as a person sitting on the Chair, you also kindly appreciate our position. The point is, it is true that we can throw out the Bill when it comes up for our aproval. But that is not the issue. The issue is, there is a definite feeling among us that the right of the hon. Member to give his opinion, at the introduction stage, as guaranteed by the rules, has somehow, been overlooked. I do not like to use the word "violated." Therefore, kindly reopen it. Let us not unnecessarily take the time of the House. We have a very important issue i.e., the Calling Attention Motion on the UTI. The country wants to know the Government's views. Kindly reopen it ...(*Interruptions*)...

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Sir, this cannot be reopened because the number of Members at that time was very few. you call for the record ...(*Interruptions*)... It cannot be reopened ...(*Interruptions*)...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Just one minute ...(*Interruptions*)...

Therefore, Sir, I appeal to you to kindly re-open the issue and take the opinion of the House...(*Interruptions*)... Sir, I appeal ...(*Interruptions*)... I appeal to you to kindly reopen the issue. Secondly, I make an humble submission that it was not proper to introduce the Bill while the Calling Attention Motion was being discussed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Mr. Gurudas Das Gupta, you were not ...(*Interruptions*)... Please ...(*Interruptions*)...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: One minute please, Sir. We are not interested in holding up the proceedings of the House. We are interested to know his views. Kindly re-open the issue and then give us the permission to know his views.

THE VICE-CHAIRMAN (Shri Adhik Shirodkar) We will take a brief recess for 15 minutes and then we will re-assemble. The House is adjourned for 15 minutes.

The House then adjourned at eleven minutes past three of the clock.

The House reassembled at twenty-four minutes past three of the clock **The Vice-Chairman (shri Adhik Shirodkar)** in the Chair

THE VICE-CHAIRMAN (Shri Adhik Shirodkar): Hon. Members, as we all know, this House is the supreme authority in all respects. As has been explained by Mr. Vayalar Ravi and Mr. Jibon Roy, this is an issue which concerns thousands and thousands of people. However, I will appeal to you that with a view to proceeding with the matters ahead of us, let us put this issue back. Let us go ahead with the work before us.

I appeal to you. Thank you very much I request Raghavji to speak now take it as if you have started now.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PIBLIC IMPORTANCE

Nav of US-64 and Status of other Schemes of Unit Trust of India Affecting Lakhs of Small Investors—contd.

श्री राघवजी (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में कहूंगा। भारतीय यूनिट ट्रस्ट एक महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था है जिसमें लाखों नहीं बल्कि करोड़ों निवेशकों का पैसा लगा हुआ है जो अपनी छोटी-छोटी बचत का पैसा इसमें जमा करके देश की वित्तीय स्थिति को मजबूत करते हैं। पिछले समय में यू०एस०-64 में जो घाटा हुआ है, वह देश के सामने आया है। इसके कारण इस सदन में यह बहस चल रही है। इस विषम परिस्थिति में मैं माननीय वित्त मंत्री जी को तीन बातों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। एक तो जो लेखा पद्धति है, उस लेखा पद्धति में सुधार करके बाजार भाव पर मूल्यांकन करके यू०टी०आई० की यू०एस०-64 स्कीम में जो घाटा हुआ है। वह घाटा सबके सामने प्रकाश में लाने में उन्होंने मदद की है वरना पहले की, 1997 तक की पद्धति में वह घाटा सामने आ ही नहीं पाता था। लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी ने नयी पद्धति

लागू करके बाजार भाव पर उसका मूल्यांकन करके यह घाटा समाज के सामने और राष्ट्र के सामने लाने में मदद की है ताकि उस पर विचार हो सके। दूसरे, मैं इस बात के लिए भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने वित्त मंत्रालय की कंसलटेटिव कमेटी में उदारतापूर्वक इस पर पूरा विचार करने का अवसर दिया और सब पार्टियों के विचारों को देश के सामने आने दिया। तीसरे, मैं इस बात के लिए भी उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस परिस्थिति से निपटने के लिए उन्होंने एक 6 सदस्यों की, विशेषज्ञों की कमेटी नियुक्त की है जिसमें पारिख साहब उसके चेयरमैन हैं जो इस विषय पर प्रतिवेदन देंगे। किन्तु यह विषय केवल यू०एस०-64 तक ही सीमित नहीं है। यू०एस०-64 का जो घाटा है वह आज की तारीख में 3366 करोड़ का घाटा है। लेकिन मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कुल जो घाटा है जो सिक्योरिटीज़ में यू०टी०आई० का पैसा लगा है, 1997 में उनका मूल्य 58634 करोड़ रुपये था, उन्हीं सिक्योरिटीज का मूल्य 30.6.98 को 48,486 करोड़ रुपये रह गया है अर्थात् कुल मिलाकर 10,148 करोड़ रुपये का घाटा केवल सिक्योरिटीज़ का मूल्य कम होने से हुआ है। इसमें यू०एस०-64 का अंश केवल 3,566 करोड़ रुपये का घाटा है। इसके अतिरिक्त जो घाटा है वह मास्टर शेयर्स-86 का 643 करोड़ रुपये का है, मास्टर प्लस-91 का 507 करोड़ रुपये का सी०जी०यू०एस०-92 का 896 करोड़ रुपये का और एम०ई०पी०-92 का 492 करोड़ रुपये का घाटा है। इससे भी दुखद बात यह है कि जो मंथली इनकम प्लान हैं, उन आठ योजनाओं में भी घाटा हुआ है और यह घाटा भी कुल मिलाकर 371 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। अब जो मंथली इनकम प्लान हैं, वह सोच-समझकर बनाए जाते हैं। उसके पैसे का भी नियमित रूप से भुगतान करना पड़ता है। इसमें भी घाटा 371 करोड़ रुपये का है। यह वास्तव में चिंताजनक स्थिति है और इसीलिए इस पर गंभीरतापूर्वक विचार होने की जरूरत है और केवल यह आठ योजनाएं मंथली इनकम प्लान की नहीं हैं बल्कि कुल मिलाकर 32 ऐसी और योजनाएं हैं जो यू०ए०-64 से हटकर हैं और इन सबमें भी आज की तारीख में 30.6.98 को कुल मिलाकर रिजर्व का घाटा 873 करोड़ रुपये का है। घाटे से निपटने के लिए यू०एस०-64 में माननीय वित्त मंत्री महोदय ने एक नयी पद्धति जो की है वह यह है कि डैप्रीसिएशन रिजर्व के अगेंस्ट में वह घाटा कम करने के कोशिश की है। उसके कारण यू०एस०-64 का घाटा 1,098 करोड़ रुपये का रह गया है। वास्तव में यह घाटा 3566 करोड़ रुपये का था लेकिन डैप्रीसिएशन रिजर्व स्कीम लागू करके इस घाटे को कम करने की व्यवस्था माननीय मंत्री महोदय ने की है। यह वास्तव में एक पारदर्शिता का प्रमाण है। इसके पहले कभी भी पारदर्शिता का मामला सामने नहीं आया। पहली बार पारदर्शिता को सामने लाकर उसकी व्यवस्था करने के चेष्टा की गयी है। वास्तव में अगर सच पूछा जाए तो यह घाटा एक वर्ष का नहीं है। यह घाटा पिछले 34 वर्षों से चला आ रहा है। यह यू०एस०-64 की योजना 34 वर्षों से चली आ रही है और मैंने जो योजनाएं बताई हैं उसमें 86 की योजना है, 91 की योजना है, 92 की योजना है, 92 की ही एक और योजना है। इन सबमें भी मिलाकर कोई 3000 करोड़ रुपये का घाटा है। इसलिए केवल इस सरकार को अगर आरोपित किया जाए तो उचित नहीं होगा। यह जो घाटे का सिलसिला है, यह पहले से चला आ रहा है। यह बात जरूर है कि शेयर मार्किट में जो गिरावट आयी है, उसकी वजह से भी यह घाटा हुआ है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से केवल एक-दो प्रश्न करना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बयान में कहा है कि यह घाटा केवल नोशनल घाटा है। मैं इसको नोशनल घाटा नहीं मानता हूं। नोशनल घाटा इसलिए नहीं है कि जब आपने एकाउंट पद्धति बदल दी है तो वास्तव में आज के बाजार मूल्य में जो घाटा है कल वह घाटा बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। कल की बात अलग है। इसलिए आज यह नोशनल घाटा नहीं है। नम्बर एक।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जो आपने विशेषज्ञ कमेटी को यह प्रकरण सौंपा है तो क्या इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि स्पेशल परपज व्हीकल योजना लागू करके US.64 का कुछ विशेष पुनर्गठन हो सके?

नम्बर तीन मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह जो मंथली इनकम प्लान है तो इस मास्टर इनकम प्लान को इतना सोच-विचार करके क्यों नहीं बनाया गया था ताकि इसमें घाटे की स्थिति न रहे? यह जो मंथली इनकम प्लान की आठ योजनाएं हैं जिनमें मंथली एनुअल रिटर्न देना पड़ता है, इन योजनाओं के बारे में आप क्या अलग से विचार करने जा रहे हैं? मैं इन दो-तीन बातों का माननीय वित्त मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं पुनः माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पारदर्शिता अपनाई है जिससे कि सारा राष्ट्र यूटीआई की वस्तुस्थिति से अवगत हो सका है। धन्यवाद!

DR. GOPALRAO VITHALRAC PATIL (MAHARASHTRA): Sir, we are creating huge financial institutions. We have got very huge funds. For example, the UTI is having about Rs.75,000 crores of investible funds. The public sector banks are having huge funds and we are making these institutions autonomous. They are under the care of only two or three people, who are either their Chairman or Directors. These people are deciding the fate of such huge funds. There are no checks and balances. Since they are autonomous, there is no accountability. There is no responsibility. Sometimes their decisions are wrong and some times the decisions are taken with a motive. Therefore, the common man, who has invested in U.T.I., is really at a loss. But the good thing is that — as we say: ignorance is bliss—these people are not at all aware that the U.T.I. is in such a crisis. The crux of the problem is that the re-purchase price of U.T.I. is slightly higher than its price. That is, the Net Asset Value is, say, about Rs. 950 paise and the re-purchase price is about Rs.14/- with a share of 20 million units, which are sold. If all people come for redemption, the total redemption amount will be Rs.28,500 crores and it will not be within the power of the U.T.I. to redeem a single coin. The net investment of U.T.I. is about Rs. 18000 crores. Therefore, the real balance of U.T.I. of Rs. 900 crores, the U.T.I. will have to find. My question is where from will it find such a huge amount? It is not that the U.T.I. is a sort of outpost of the Finance Ministry. Of course, sometimes is work on the bidding of the Finance Ministry. For example, when the shares fall, the U.T.I. is called upon to intervene to purchase the shares of various public sector units; and, sometime even of the corporate sector. There is a long-standing understanding between the U.T.I. and the various corporate sectors. For example, a mention was made that with one big corporate unit, Reliance, U.T.I. purchased a huge block of shares at a very high price, say, at more than Rs.400 per share. Soon it realised that its price was not so much. It was actually less than Rs.200. So, such huge losses are sustained by the U.T.I. I would like to know whether it was a correct decision of the Chairman of the U.T.I.

Those who are managing the UTI, what is their accountability? I would like to know whether there is any control of the Government. Is there any transparency? These are the issues which are more important. Now, a problem has cropped up that the Net Asset Value of the UTI had dropped. It had sustained a huge loss. The question is: How to rebuild it? The debate here is to highlight the importance of the US-64, and not create a scare among the people who have purchased it or the people who are likely to purchase. May I know from the hon. Minister what steps the Government would take to instill confidence in the minds of the people on the schemes of the UTI? There had been a suggestion that some financial institutions, particularly, the Reserve Bank of India, the State Bank of India and other nationalised banks should come forward to help the UTI.

By accepting this suggestion, are not spreading this rot to other financial institutions? They will only be sharing losses of the UTI and US-64. Therefore, a policy has to be evolved to create a fund either through the budgetary support or, as many of our hon. Members suggested, a special purpose vehicle can be created. From that the Government and many PSUs can invest in this fund. Through this fund the UTI should be managed. Then only the rating of the UTI can be enhanced to instill confidence in the minds of the people who have purchased units. Therefore, the Government should intervene immediately to prevent this crisis so that it may not spread to other financial institutions to cause a collapse.

Sir, I thank you for having given me this time to speak on this Calling Attention matter.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Thank you Dr. Patil. Now, Mr. Vayalar Ravi.

SHRI VAYALAR RAVI (KERALA): Mr. Vice-Chairman, at the very outset the statement of the hon. Minister is a big coverup. He never told us the full truth. I would like to quote from the third para of the Minister's statement: "As on 30.6.98 when the balance-sheet of US-64 was drawn, it was found that there was depreciation in the value of investment to the tune of Rs.3566 crores. Sir, even a country like Malaysia is suffering capital outflow. You know what happened. Likewise, it happens here in a serious. The problem is there in the whole world. India itself is evidence of it. But this management could not understand it; As Mr.Gurudas Das Gupta has said, the audit pointed out what happend for the last two or three years. There is another sentence in the statement of the Minister, "The sale and repurchase price of US-64 are not solely based on the net asset value (NAV), but also on the need to protect the value of investment at the time of repurchase by the unit holder and reasonable return on their investment". What do you mean by 'reasonable return'? What is a reasonal return? As Mr. Patil has already stated, the value is Rs.950 and you are purchasing at Rs.14.30. Who will fill the gap? Where do you get the money from? Who benefits by this? The Government is not benefiting; your Budget is not benefiting; the UTI is not benefiting; the investor is not benefiting. The benefit goes to certain companies, certain big business houses. They are benefited because by this artificial, inflated, rate you are maintaining some kind of prestige of some big business house to maintain their industry, to make them them earn profits. It is not in the interests of the investor. What is the whole prupose of this 'Special Purpose Vehicle' and making such an inflated value? To help whom is it done? I want an answer from the hon. Minister. Whom do you want to help? It is the investor or the UTI or the Government or some monopoly house? This is one point.

Many hon. Members spoke about the leakage. I do not want to repeat what they said. That is a very serious allegation. Very responsible Members of both sides of the House have made this very serious allegation of leakage of every decision of the UTI. How to prevent it? It is not a question of the Minister alone; it is a question of this Parliament itself; it is a question for every one of us. We are not looking at it on a partisan basis. It means there are some top-ranking officers of the UTI or the agents of big business. How pays them? Do you pay them or does the business. Who pays them? Do you pay them or does the business pay them? Who pays them? Many questions have been raised. Many questions have come up on this issue of cover-up and the crisis in the UTI where the investor has lost, the UTI has lost, the Govenment has lost and the capital market has suffered. As you know, as a major player in the capital market, the UTI was to know that. Anything that happens to the UTI can not only create a problem in the capital market but it will have a reflection in the rational economy also. I want to know this from the hon. Minister. Apart from the short-term measures, what are the long-term measures that you are taking to set right the issues in the UTI?

Apart from that, it is said that the loss is only Rs.1098 crores. Please tell us, at least this House, what the total loss suffered by the UTI is. It is not just Rs. One thousand crores. It is more than that. We know that. Who is responsible for the loss? In fact, it will be more than what Mr.Gurdas Das Gupta, Mr.Patil and others mentioned. Let us know who is responsible for such a heavey loss that happened for the last 2-3 years to the UTI and in turn to the investor. Where

did not invest all this money? You please find out that also. What are the criteria for investing the money? The UTI money is invested to create certain monoply houses, to help certain monopoly houses. The not only invest money; then they protect them. They protect the value of the shares. They become a burden of the UTI. They are shouldering that burden. They not only invest money but also protect the share value of these business houses. What is this functioning? Will you please inquire into it? It requires a special audit at least for the sake of the future, for the sake of the existence of the institution, for the sake of the protection of the investor. On the basis of your own statement, as given to you or briefed to you by the officers, they found, only after the audit has been made, that there was loss. It means that the most incompetent people are sitting at the top in the institution. Otherwise, the people who play in the capital market are expected to know the trend of the market.

They are expected to know the trend. I hope the Minister will answer all these questions while replying to the debate. Lastly, will you order a special audit into the functioning of this institution to find out how this money has gone out? What are you going to do to rectify the situation? What is your long-term plan and what are you going to propose? will you intervene to see that the Special Purpose Scheme shall not be used to inflate the price, which is not the real value, and further dupe the investors? Thank you.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, the lower middle class people as well as those people who have invested their money in various US-64 schemes are thinking as to what would be the outcome of the discussion we are having in this august House. The US-64 scheme has been in existence in our country for the last more than 22 years. When it is so, how has it become a subject matter of discussion? It is because of the wrong policies pursued by the UTI itself. My colleagues have clearly mentioned about this fact. I don't want to repeat those things. First of all, we have to take into account two things. Firstly, the UTI administration has to be revamped. Secondly, the discussion should not create any panic in the minds of those people who have invested their money in various UTI schemes. I would like to make a few submissions in this respect. Firstly, the UTI does not come under the purview of the principal capital market regulator, that is, SEBI. If the UTI had been kept under the purview of SEBI, the mistakes committed by these people would have come to the knowledge of the people. But it is not so. It is working under a separate statute. The supervisory powers or the structural arrangements are not enough. This has been shown by the recent happenings. How will you find out the market value of the unit unless there is transparency in the scheme? But this is the only scheme in which we find that the transparency door has been closed. You are speaking about transparency in every sphere except the UTI. What has been the result? The net asset value has remained hidden and it has not been made public. If this is so, in that event, we are unable to understand as to what the market value of that unit is. Unless the actual market value of the unit comes to the knowledge of the public, people cannot know about it and the institution can't function in a profitable manner. Secondly, the reply comes in the negative. They attribute so many factors for this negative reply. They are required to go through the price of the scrips as well as its intrinsic value. In 1993-94, the reserve account had shown a figure of Rs. 5,842 crores. During 1996-97, this figure, had depleted and came down to Rs. 1778 crores. What does this show? Those who have invested their money, the dividend has been given to them out of this income. That means the income derived by them was not sufficient to pay the dividend which was announced by the UTI. The UTI has a nominated director.

There are about 3100 companies who have invested their money in it. Now the computer has come to stay in our land. When more than 3,100 companies are having interaction, they should have made an earnest effort to find out as to what is going on in the companies through the Government nominee director. Under what norms are the nominee directors functioning? Whether these norms are sufficient to enable them to perform their functions in an effective manner. The hon. Finance Minister has to go through the entire thing. Had the nominee directors given the proper picture of the company in which they were nominated to the UTI, this type of a situation would not have arisen at all. That is my opinion.

Then I come to the question of personal gains. I feel that the people who are holding high positions, dominate the public interest. On 25th September they had signed the balance-sheet. When it was signed on 25th September, how was it reflected in the stock market on 28th September itself before it was officially announced? Within three days, it affected the stock market. What does it show? It justified the accusation made by some hon. Members that a deliberate leakage was there. This leakage was like an inside trading. It has taken place. It is a very dangerous thing for any institution. What I feel is that instead of an arbitrary determination of unit prices, we must find out some norms by which they must understand the market value of the unit. For that purpose, the Government should come forward. The distortion between income and dividend has to be taken into consideration. For example, in 1994-95, the income was Rs. 3,287 crores. But the disbursement was Rs. 3,973 crores. How has the reserve account depleted? They had mentioned it in respect of the year 1997-98 because it was plus point for them. That was why they had mentioned it. But if you go through the figures of last three years, you will find that even to pay the dividend, they had resorted to the reserve fund. The income was not sufficient to pay the dividend. This is the situation which is prevailing there. We are able to put some pressure on the non-banking finance companies. We are able to take legal action. What type of action are we going to take against the people who have committed not an error but a mistake? Some people have committed a mistake, not an error. Therefore, those who have committed mistakes should be brought before the Bar and the law of the land should take its course so that they may not repeat the same thing in future. I am pointing this thing out because this is going to be continued. Now, I would like to refer to the "Business Standard" of today, the 2nd December, 1998. I would like to quote a few lines from the "Business Standard". It says:

> "The unit capital of US-64 for year ended June 30 stood at Rs. 15629.70 crore. As against this the capital as on June 30, 1997 stood at Rs. 14028.15 crore.
>
> Apart from the flagship of UTI, there were 32 other schemes, including its assured return schemes, whose reserves as on June 30 turned negative.
>
> The aggregate deficit of these 32 schemes stood at Rs. 873 crore, compared to a positive reserve of Rs. 335 crore in June 30, 1997. This makes the total deficit of the fund to Rs. 1,971 crore." Sir, this is the situation. What I feel is that a Commission of Inquiry should be instituted. (*Interruptions*) Mr. Gurudas Das Gupta is saying that at least a Parliamentary Inquiry should be instituted. After it has submitted its report, if we feel that the Commission of Inquiry is necessary, we can institute that also. What I feel is that the UTI has lost the confidence of the public. With these words, I conclude.

श्री रामदेव भंडारी (बिहार): उपसभाध्यक्ष जी, मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि 30/6/98 की स्थिति के अनुसार जब यू०एस० 64 का तुलना-पत्र तैयार किया गया, तो यह पाया गया कि निवेश के मूल्य में 3566 करोड़ रुपए का ह्रास हुआ है। दूसरी ओर मंत्री जी ने यू०एस० 64 योजना के बारे में यह भी कहा कि 34 वर्षों से इस योजना ने छोटे-छोटे निवेशकों का एक बड़ा आधार तैयार कर लिया है और जून 1998 तक 21738 करोड़ की परिसंपत्तियां तथा 21 मिलियन निवेश का आधार तैयार कर लिया गया है।

महोदय, इस देश में मध्यम और छोटे निवेशकों की एक बहुत बड़ी जमात है और वह चाहते हैं कि बड़ी कठिनाई से कमाई गई अपनी रकम को किसी ऐसे स्थान पर लगाएं जहां कि उन की पूंजी भी सुरक्षित रहे और उस का सही लाभ भी मिलता रहे। इधर कुछ महीनों से नॉन-फायनेंसियल कंपनीज के बारे में जैसी खबरें आ रही हैं और उन में लोगों का करोड़ों-करोड़ रुपया डूब रहा है, गिरफ्तारियां हो रही है, मुकदमे हो रहे हैं, उस तुलना में यू०एस० 64 ने अपना एक बहुत ही सम्मानित और प्रतिष्ठित स्थान बनाया था जिस कारण निवेशकों का यू०एस० 64 में पूरा विश्वास बना हुआ था। मंत्री जी ने यह बात अपने वक्तव्य में भी कही कि उस के निवेश में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मगर कुछ महीनों से यू०एस० 64 के बारे में जो कुछ खबरें अखबारों में आ रही हैं, उस कारण उस की विश्वसनीयता को एक जबर्दस्त धक्का लगा है और निवेशकों को भी बैचेनी हो रही है कि हमारी जो पूंजी लगी हुई है, वह पूंजी सही-सलामत रूप से वापिस आएगी या नहीं?

महोदय, यह एक कठिन परिस्थिति है। एक तरफ यू०एस० 64 की विश्वसनीयता को बचाना है। सरकार को यह भी देखना पड़ेगा कि आखिर क्या कारण है कि 1994 से इस में इरोजन शुरू हो गया और इन कई वर्षों में इस संबंध में निवेशकों को क्यों अंधकार में रखा गया? उन्हें सही जानकारी क्यों नहीं दी गयी? आखिर वह कौनसी परिस्थिति थी कि इस बात को छिपाया गया? इस की जांच होनी चाहिए। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप इस बारे में जांच कराएं। इस के अतिरिक्त हमारे कई माननीय सदस्यों ने इस में "लीक" की चर्चा भी की है कि जब भी खरीदने या बेचने की कोई योजना बनती है तो कहीं-न-कहीं से यह बात "लीक" हो जाती है और इस के जो कांपीटीटर्स हैं, उन को इस का फायदा मिल जाता है। साथ ही इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि क्या यू०टी०आई० में किसी तरह का फंड मिस-मैनेजमेंट है?

महोदय, एक बात और जानना चाहता हूं कि यू०एस० 64 को बिल्कुल सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए क्या सरकार के पास कोई योजना है क्योंकि इस की मजबूती बहुत जरूरी है? सरकार की ओर से या बैंक की ओर से कोई काउंटर-गारंटी है या नहीं? मंत्री जी अपने जवाब में बताएं कि यू०एस० 64 को मजबूत किस तरह से किया जाए? इस बारे में उन की क्या योजना है, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अत्यंत ही आभारी हूं उन सभी सदस्यों का जिन्होंने इस बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया और अनेक महत्वपूर्ण बिंदु सरकार के ध्यान में लाए। मैं आभारी हूं विशेषकर गुरुदास दासगुप्त जी और विरेंभि जी का जिन्होंने इस बात पर बल दिया कि हमें यहां ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए या कुछ नहीं करना चाहिए जिससे कि निवेशकों के विश्वास में कमी आए। यह दूसरी बात है कि गुरुदास दासगुप्त जी ने जो कुछ कहा, ठीक उसके उल्टे अपनी बात कही, लेकिन इस तथ्य को उन्होंने स्वीकार किया। मैं मानता हूं, उपसभाध्यक्ष महोदय, हम जिस बेलेन्स-शीट की बात कर रहे हैं यू.टी.आई. की, वह 30 जून, 1998 की बेलेन्स-शीट की बात कर रहे हैं। इस 30 जून, 1998 में इस सरकार को आए मात्र तीन महीने हुए थे और इसलिए मेरे लिए बहुत आसान है खड़े होकर इस माननीय सदन में कह देना कि जो कुछ यू.टी.आई. में हुआ है, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं क्योंकि यह यू०एस० 64 स्कीम 34 वर्षों से चल रही है और यह सारा कबाड़ा तीन महीने में हो गया, ऐसा कोई मानने को तैयार नहीं है। माननीय सदस्यों ने भी यहां कहा है कि रोग या बीमारी पुरानी है और इसकी तह में जाने की आवश्यकता है। मैं वह आसान रास्ता नहीं ले रहा हूं और वह आसान रास्ता इसलिए नहीं ले रहा हूं इस सिद्धांत के अलावा कि सरकार जो है वह एक नियमित चलने वाली चीज है, शाश्वत चलने वाली चीज है। उसके अलावा मैं अपने विश्वास के आधार पर, अपनी आस्थाओं के आधार पर भी यहां यह कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि यू०एस० 64 में या यू.टी.आई. में ऐसी कोई बात नहीं है, जिसके चलते सदन के माननीय सदस्यों का या देश की जनता जो यू.टी.आई. में निवेश करती है उसका, विश्वास टूटे। ऐसी कोई बात नहीं है। जब यह सारा मामला आया, जो प्रश्न उठाए गए हैं, जो संदेह यहां पर व्यक्त किए गए हैं, वह सारे के सारे मेरे मन में भी पैदा हुए क्योंकि मैं भी कोई एकाउण्टेण्ट नहीं हूं। कुमार साहब इसके विशेषज्ञ हैं, मैं नहीं हूं विशेषज्ञ। मेरे मन में भी वह सारे सवाल उठे कि

आखिर ऐसा क्या हो गया अचानक यू.टी.आई. में, कि इतना बड़ा घाटा हो गया और जिससे देश के लोगों का, निवेशकों का विश्वास इससे टूटता जा रहा है। मैं भी घबड़ाया, लेकिन जब मैं उसकी तह में गया तब मुझे पता चला कि उसमें कोई विशेष बात नहीं थी। ...(व्यवधान)...

SHRI GURUDAS DASGUPTA: Why are you speaking in Hindi?

श्री यशवंत सिन्हा: मुझे यह सिद्ध करना है कि मैं हिन्दी में भी बोल सकता हूं।

श्री आर०के० कुमार: बोलिए, साहब। जो हिन्दी नहीं बोलते हैं उनको भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद आता है। आप हिन्दी में बोलिए। ...(व्यवधान)...

प्रो० रामगोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): आप तो अंग्रजी से भी अच्छा बोल सकते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री यशवन्त सिन्हा: इसलिए, उपसभाध्यक्ष महोदय, जैसा मैं कह रहा था, क्या हुआ यह कि हर साल की भांति इस वर्ष भी 30 जून को यू०टी०आई० का जो सालाना एकाउंट है, लेखाजोखा है, वह तैयार करना था। यह 30 जून रेफरेन्स डेट है, उसका जो वर्ष है, वित्तीय वर्ष यू०टी०आई० का, वह 1 जुलाई से 30 जून तक रहता है। इसमें जब यह लेखाजोखा तैयार हो रहा था तो उस समय पाया गया कि 30 जून को जो स्टाक मार्केट में उसका वेल्यू था, इन शेयर्स का, उसमें कमी हुई है। गिरावट हुई थी, मैंने कहा है अपने वक्तव्य में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई थी। तो जब उसमें गिरावट हुई तो उस गिरावट को कहीं न कहीं हमें अंकित करना पड़ेगा, अपने हिसाब-किताब में उस गिरावट को शामिल करना पड़ेगा। मेरे ध्यान में पहले यह बात आई, जैसी यहां के माननीय सदस्यों के ध्यान में आई, कि मुम्बई के शेयर बाजार में शेयर में उतार-चढ़ाव होते रहे हैं, वर्षों से होते रहे हैं, इस साल कौन सी विशेष बात हो गई कि इस उतार-चढ़ाव के चलते हमें इतना घाटा देखना पड़ा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं देख रहा था, हमारे गुरुदास दासगुप्त जी और इस माननीय सदन के अन्य सदस्य भी उस ज्वायंट पार्लियामेंटरी कमेटी के, संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य थे, जिन्होंने उस पूरे घोटाले में उसकी जांच की थी। गुरुदास दासगुप्त जी उस समिति से एक बहुत बड़े विशेषज्ञ होकर निकले। मैं नहीं निकला। मैं आज भी अपने को शेयर मार्किट का विशेषज्ञ नहीं मानता हूं, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि मेरे पास आंकड़े हैं, सितम्बर, 1994 में मैं देख रहा था कि मुम्बई का सेनसैक्स 4,604.15 पर था। वह घटते-घटते दिसम्बर, 1996 में कहां आ गया? वह आ गया 2,798 पर। यह गिरावट आ गई। 4,604 में घटते-घटते वह आ गया 2,798 पर, लगभग सवा साल में। तो उतार-चढ़ाव हुआ है शेयर बाजार में इससे पहले भी। यह क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हुआ यू०टी०आई० में? यू०टी०आई० की यू०एस०-64 या जो दूसरी स्कीम हैं, उस समय भी उनके शेयर का कोई न कोई मापदंड था, कोई वेल्यू थी, कोई मूल्य था, तो यह रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ रिफ्लेक्ट कि 30 जून को जब हम उसका लेखा-जोखा कर रहे थे, उस दिन यह नहीं हुआ, सितम्बर में होगा, दिसम्बर में, जनवरी में होगा, लेकिन 30 जून को नहीं था। इस साल हम 30 जून का ले रहे थे और जैसा कि कुमार साहब कह रहे थे, अपने विशेषज्ञ ज्ञान के आधार पर, कि एक जिसको प्रूडेंट फाइनेंशियल नॉर्म्स कहते हैं, उसको यू०टी०आई० ने फॉलो करने का, अनुकरण करने का प्रयास किया और इसीलिए उसमें जो चढ़ाव आता है, जो एप्रीसिएशन होता है, उसको हम रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं लेकिन प्रूडेंट फाइनेंशियल नॉर्म्स का तकाजा है कि यदि उसमें घाटा हुआ है, डेप्रिसिएशन है तो उसको हम रिफ्लेक्ट करें और इसलिए 30 जून को क्योंकि शेयर बाजार में गिरावट थी उस दिन तो इसलिए उसको हमने रिफ्लेक्ट किया। उसको रिफ्लेक्ट करने का नतीजा क्या हुआ? वह 3566 करोड़ रुपया, जो हमने बताया कि उस दिन के हिसाब से यह घाटा दिखा, उसको हमने रिज़र्व में रिफ्लेक्ट किया। रिज़र्व जो यू०टी०आई० के पास पहले से थे, उसके आधार पर एक हजार कुछ करोड़ का, जो मैंने अपने वक्तव्य में अंकित किया है, यह रिज़र्व में घाटा आया।

इसके साथ ही दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह यह है कि इस साल जो भी हमने मुनाफा दिया, डिविडेंड दिया यूएस-64 का, वह उनकी जो आमदनी थी इस साल, उसमें से दिया, हमने रिज़र्व में से ड्रा नहीं किया, इन्कम में से दिया। इसलिए ऐसा नहीं मानकर चलना चाहिए कि पता नहीं कितने हजारों करोड़ का घाटा यू०टी०आई० को हो गया और बड़ी भारी आफत आ गई। मेरे माननीय मित्र गुरुदास दासगुप्त जी ने और कुछ अन्य सदस्यों ने तो यहां तक कह दिया कि स्केंडल है, स्कैम है और पता नहीं क्या-क्या। घाटा नोशनल है, मैं बार-बार कह रहा हूं कि घाटा नोशनल है, घाटा काल्पनिक है। काल्पनिक कैसे है, आज के दिन अगर आपने 100 रुपए में कोई शेयर खरीदा है, कल उसकी कीमत 50

रुपए पर आ जाती है तो आपको 50 रुपए का घाटा हो गया, यदि बेचने जाते हैं तब। यदि आप बेचने नहीं जाते है, आप इंतजार करते हैं तो हो सकता है कि कल को यह शेयर 125 रुपए हो जाए और 125 रुपए में जब आप बेचेंगे तो आपको 25 रुपए का फायदा होगा यदि आप 50 रुपए में बेचेंगे तो आपको 50 रुपए का घाटा होगा। अब जो लोग शेयर बाजार की जानकारी रखते हैं, वे कैसे इसकी व्यवस्था करते हैं, यह वे जानें लेकिन नोशनल इस मायने में है कि अगर हम इसको बेचने जाएंगे तो हमें यह घाटा सहना पड़ेगा। लेकिन 30 जून को चूंकि यह घाटा था इसलिए इसको बेलैंसशीट में हमें रिफ्लेक्ट करना था, दिखाना था और इसलिए यह हमने काल्पनिक घाटा उसमें दिखाया हुआ है। अब क्या है इसमें? यहां प्रश्न उठाया गया कि किस तरह यू०टी०आई० इन्वेस्ट करता है, उसकी जांच होनी चाहिए। इसके पहले कि मैं इन बातों की ओर ध्यान आकृष्ट करूं, मैं दो-तीन जो तथ्यात्मक बातें हैं और जो भूल मेरे माननीय साथियों से हुई है, मैं उनकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पहली बात, यू०टी०आई० पार्लियामेंट के, संसद के कानून के तहत बनाई हुई एक संस्था है, स्टेच्युटरी बॉडी है लेकिन हम उसके शेयर होल्डर्स नहीं हैं, प्रेजीडेंट आफ इंडिया उसके शेयर होल्डर्स नहीं हैं आई०डी०बी०आई० और रिज़र्व बैंक उसके शेयर होल्डर्स हैं, वे इसके मालिक हैं, वे चलाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि गुरूदास दासगुप्त जी ने जो बड़े जोर से यहां प्वाइंट उठाया कि What were the directors of the Finance Ministry doing? उनको पकड़ो, फाइनेंस मिनिस्ट्री का कोई डायरेक्टर नहीं है यू०टी०आई० में। ...(व्यवधान)...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I said, 'also RBI'. RBI is completely under Government...

SHRI YASHWANT SINHA: No, it is not.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Why? What is it?

SHRI YASHWANT SINHA: RBI is an autonomous organisation. Shri Pranab Mukherjee, the hon. former Finance Minister is sitting here. Let him say that ...*(Interruptions)* Let him say that RBI is the creature of the Government...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: That is not the issue. The Government can implement the policies through the RBI. It is always...

SHRI YASHWANT SINHA: RBI is an autonomous organisation. RBI sets its own policies.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: It is an imaginary argument...

श्री यशवंत सिन्हा: ये इमैजिनरी आग्यूमेंट नहीं है।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: If the RBI is beyond your arm, control and influence, then nothing is within you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI)! He said that it is a statutory body.

श्री यशवंत सिन्हा: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि आर०बी०आई० और आई०डी०बी०आई० इसके शेयरहोल्डर्स हैं, इसलिए सरकार का उसमें कोई डॉरेक्टर, ट्रस्टी नहीं है और इसीलिये यह कहना कि सरकार का ट्रस्टी क्या कर रहा था, अपने आप में सही नहीं है क्योंकि वहां हमारा कोई ट्रस्टी नहीं है। दूसरा तथ्य यह है और मैंने अपने बयान में खुद कहा है कि 2 करोड़, 10 लाख लोगों का निवेश उसमें लगा हुआ है और वे बहुत छोटे-छोटे निवेशक हैं लेकिन इसमें प्रोविडेंट फंड का पैसा नहीं लगा हुआ है। यू०टी०आई० में प्रॉविडेंट फंड के पैसे को लगाने पर मनाही है।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I am again disputing it. He does not know it. There are exempted dividends, and exempted dividend money is put in US-64.

The hon. Finance Minister does not know it...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Mr. Minister, you take your seat. He is saying something.

SHRI YASHWANT SINHA: You cannot ask me to take my seat.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): But he is getting up and speaking. I can allow only one person.

श्री गुरूदास दासगुप्ता: ऐक्जम्पेड प्रोविडेंड फंड है या नहीं, यह बताइए।

श्री यशवंत सिन्हा: आपने प्रॉविडेंट फंड का बात की थी।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Exempted provident fund is also a provident fund and they are heavily invested in US-64. The hon. Minister should know this.

श्री यशवंत सिन्हा: मैं अपनी बात पर अभी भी अड़ा हूं कि Provident funds are not allowed to be invested in UTI schemes. That is it.

उसके बाद कहा गया कि यू०टी०आई० के जो एकाउंट्स हैं, वे ऑडिट नहीं होते है। महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि 1964 से लगातार यू०टी०आई० के एकाउंट्स की ऑडिटिंग कराई जाती रही है ऑडिटर्स के द्वारा और वह ऑडिटर सरकार नहीं बहाल करती है, वह ऑडिटर व्यवस्था के तहत रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बहाल करता है और इन ऑडिटर्स की रिपोर्ट को हर साल, भारत सरकार के गजट में हम प्रकाशित करते हैं। इसीलिए कोई भी बात छिपी हुई नहीं है।

एक बात और कही गई माननीय सदस्यों के द्वारा, जैसे अभी आर०बी०आई० के बारे में भी कही गई कि हम यू०टी०आई० को निर्देशित करते हैं, हम उन्हें कहते है कि यह शेयर खरीदो, वह शेयर खरीदो। मैं यह कहना चाहता हूं कि इन 8 महीनों में जब से मैं वित्त मंत्री हूं इस सरकार का, मैंने यू०टी०आई० को कभी कोई निर्देश नहीं दिया है कि तुम यह खरीदो, तुम वह खरीदो। इस तरह की बातें भी मेरे ध्यान में नहीं है कि मेरे पूर्ववर्ती वित्त मंत्रियों ने भी इस तरह का कोई निर्देश यू०टी०आई० को दिया है। इसलिए यह कहना कि यू०टी०आई० हमारी दासी है, हम जैसे चलाएंगे वैसे ही उसे चलना होगा, मैं इसे मानने को तैयार नहीं हूं। यू०टी०आई० एक स्वतंत्र संस्था है। हम उसके कामकाज में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं और हस्तक्षेप करने के लिए न कोई जानकारी रखना चाहते हैं। यू०टी०आई० का पैसा यदि बंबई के शेयर मार्केट में लगा हुआ है तो उसके जो फंड मैनेजर्स हैं, वे ही उसको मैनेज करते रहे हैं और आगे भी करेंगे। मैं सरकार की तरफ से इस बात को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं हूं कि हम यू०टी०आई० के इन्वैस्टमेंट डिसीजंस पर हावी हो जाएंगे। हम उन पर हावी नहीं होंगे और मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि पार्लियामेंट को भी और इस सदन को भी उससे दूर रहना चाहिए क्योंकि अगर वहां कोई गड़बड़ी होती है तो हम उसके भागीदार नहीं हैं। वह उनका अपना डिसीजन है। अगर सही डिसीजन है तो वे जानें, गलत है तो वे जानें। हम उनके बदले खड़े होकर कहें कि तुम इसमें इन्वैस्ट करो, उसमें इन्वैस्ट करो, यह सही नहीं होगा। इसलिए हम इस बात को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं।

महोदय, यहां पर यह कहा गया कि यू०टी०आई० का नियंत्रण किसके हाथ में है? मैंने कहा कि यू०टी०आई० संसद के विधेयक के तहत बनी हुई एक संस्था है। इसलिए ज़ाहिर है कि पार्लियामेंट का कंट्रोल इस पर है। अगर पार्लियामेंट का इस पर कंट्रोल नहीं होता तो हम इस विषय पर आज यहां चर्चा नहीं करते और न मैं मंत्री की हैसियत से खड़ा होकर आपके सवालों का जवाब देता। पार्लियामेंट का इस पर कंट्रोल है चूंकि यह एक स्टैच्युटरी बॉडी है और इसलिए यह एकाउंटेबल है। लेकिन यह एकाउंटेबिलिटी किस तरह की होनी चाहिए? उसकी एकाउंटेबिलिटी का जो चरित्र है, वह हम सबको मिलकर तय करना है। जैसा मैंने कहा कि हम इसके हक में नहीं हैं कि हम यू०टी०आई० की पीठ पर सवार हो जाएं और उसके हर फैसले को नियंत्रित करें और कहें कि यह फैसला होना चाहिए। महोदय, यहां "सेबी" की बर्किंग की बारे में भी बात उठाई गई है। महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि 1993 में यू०टी०आई० के बोर्ड ने एक समिति गठित की थी जिसके अध्यक्ष श्री एन० बागुल थे। उस समिति ने पूरी जांच-पड़ताल की कि "सेबी" का नियंत्रण यू०टी०आई० के ऊपर कैसे होना चाहिए और उन्होंने यह कहा कि यू०टी०आई० में दो तरह की स्कीम्स चल रही हैं—एक प्योर इक्विटी स्कीम है और दूसरी है सेविंग्ज स्कीम। They are in the nature of saving schemes. इसलिए उन्होंने कहा कि जो इक्विटी स्कीम्स हैं, जहां पर यू०टी०आई० म्युच्अल फंड की तरह काम करती है, उसको "सेबी" के नियंत्रण में लाया जाए। इस पर विचार किया "सेबी" के बोर्ड ने और इसको स्वीकार किया और 1994 के जुलाई बाद से यू०टी०आई० बोर्ड "सेबी" के इन सारे रेगुलेशंस को मान रहा है और मार्केट रेगुलेटर "सेबी", यू०टी०आई० के कामकाज पर नियंत्रण करता है। इसलिए यह कहना कि वह बाहर है, यह सही नहीं होगा।

महोदय, अब स्थिति क्या है? अब स्थिति यह है कि यू०टी०आई० में 77 स्कीम्स चल रही है जिसमें से 6 ऑफ-शोर फंड्ज हैं और 71 डोमेस्टिक फंड्ज है जिनमें नैट ऐसेट वैल्यू के आधार पर 30 स्कीम्स चलती हैं और बाकी की जो 41 स्कीम्स हैं और वह ऐश्योर्ड रिटर्न स्कीम्स हैं। जब हम काम कर रहे थे ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी में, तो एक सबक वहां हमने यह सीखा कि जो पैसा मार्केट में शेयर बाजार में इन्वैस्ट होता है, उसमें फिक्स्ड रिटर्न नहीं हो सकती है। जाहिर है जब आप

शेयर बाजार में खेल रहे हैं तो वह कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा, उसको आप फिक्स कैसे कर सकते हैं? इसलिए फिक्स्ड रिटर्न स्कीम में अगर इक्विटी का कोई पोर्शन है, एक अंश है, जैसे यू०एस० 64 में मैंने कहा कि 64 प्रतिशत है, अगर इक्विटी का कोई अंश है भी तो उसके बाद भी वह फिक्स्ड रिटर्न स्कीम है और पूरी तरह से इक्विटी नहीं है, पूरी तरह इक्विटी बेस्ड नहीं है, पूरी तरह से म्युच्अल फंड नहीं है। अब जो फिक्स्ड रिटर्न स्कीम है, जिसमें यू०एस० 64 भी आता है, उसमें भी नोशनल ऐसेट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि—

> "The application of stock market prices for valuation of equity would result in substantial volatility as a result of which it would be difficult to maintain gradually rising prices from the low in July every year to the peak of May in the next calender year when the accounts will come. There is difficulty in properly valuing term loans and real estate investment since market quotes are not there Adoption by UTI of strict RBI income recognition and provision on norms for valuation on non-performing assets for which no market exists and inability of stock market prices to reflect real value of substantial holdings of US-64 in many companies since, these instruments are in the nature of long-term strategic investment especially in shares, in public sector and financial sector."

इसलिए 1964 से आज तक कितने ही उतार-चढ़ाव आते रहे मार्केट में लेकिन क्यों नहीं नैट ऐसेट वैल्यू का सवाल उठा यू०एस० 64 के बारे में या यू०टी०आई० की किसी दूसरी स्कीम के बारे में? उतार-चढ़ाव को हम सब जानते हैं। हम जानते हैं कि कितना हो गया था 1992 में और उसके बाद कितना नीचे गया, वह भी हम सब जानते हैं। उसके बाद भी आज तक नैट ऐसेट वैल्यू का सवाल यू०एस० 64 के बारे में जो स्कीम 1964 से चल रही है, क्यों नहीं उठाया गया? क्योंकि पारदर्शिता नहीं थी। जैसा कुमार साहब अभी कह रहे थे, पहली बार पारदर्शिता हमने दिखाई तो हमें ही दोषी ठहराया जा रहा है। मेरे ऊपर दोष लगाया जा रहा है कि पारदर्शिता क्यों दिखाई? मैं आपसे सहमत हूं कि चाहे वह यू०एस० 64 हो या यू०टी०आई० की दूसरी स्कीम्स हो, उन्हें पारदर्शिता के आधार पर काम करना होगा। और वही प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है कि यह पारदर्शिता उसमें हो और उसमें जहां कहीं कमी होगी, उस कमी को हम निश्चित रूप से दूर करेंगे लेकिन उपसभाध्यक्ष महोदय, इसमें हमने क्या कहा? हमने नहीं कहा, यू०टी०आई० के बोर्ड ने स्वयं फैसला किया, जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि हम एक कमेटी बनाएंगे और आज तीन ऐसेट मैनेजमेंट कमेटीज़ यू०टी०आई० बोर्ड ने बना दी कि हर ऐसेट के ऊपर विचार करो और हमें सुझाव दो कि क्या करना है? दीपक पारिख कमेटी जो बनी है बोर्ड के द्वारा, वह देख रही है यू०एस० 64 को। यहां पर अखबारों में कुछ खबर छप गई पता नहीं कहां से कि कोई स्पेशल परपज़ व्हीकल दीपक पारिख कमेटी सोच रही है। दीपक पारिख कमेटी के सुझाव अभी प्राप्त नहीं हुए हैं और इसलिए अखबारों में कोई चर्चा हो जाए, उसके आधार पर यहां चर्चा शुरू कर दें, वह सही नहीं है। स्पेशल व्हीकल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इन सब बातों पर यू०टी०आई० का बोर्ड विचार करेगा जब दीपक पारिख कमेटी की सिफारिशें आ जाएंगी और उसके बाद मुझे पूरा विश्वास है कि वे उचित फैसला करेंगे। पार्लियामेंट को, सरकार को हक है कि अगर हम समझें कि उचित फैसला नहीं हो रहा है तो हम उसमें हस्तक्षेप करें और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि निवेशकों के और विशेषकर छोटे निवेशकों के हक में जो कुछ भी करना पड़ेगा, उसको करने से सरकार कभी भी हिचकिचाएगी नहीं, कभी भी कतराएगी नहीं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यहां पर कई प्रश्न उठाए गए। जनेश्वर मिश्र जी अभी मौजूद नहीं हैं लेकिन उन्होंने कहा कि दो टके पर किसी कंपनी ने उनसे लोन ले लिया और उसी को सोलह टके पर इनवेस्ट कर दिया। मैंने पता करने की कोशिश की, मेरे ध्यान में इस तरह का कोई वाकया नहीं है कि दो टके पर लिया और सोलह टके पर उसको इनवेस्ट कर दिया है।

एक बात जो गुरुदास दासगुप्त जी ने उठाई थी, वह यह भी थी कि उन्होंने किसी खास कंपनी के कुछ शेयर्स खरीद लिए थे, प्राइवेट प्लेसमेंट किए थे और जहां तक मेरा ज्ञान है क्योंकि मैं भी इस सदन का सदस्य कुछ दिनों तक था कि यह सवाल बार-बार दोनों सदनों में उठाया गया है और तत्कालीन जो सरकारें थीं, उनके वित्त मंत्रियों ने, मेरे समय के नहीं, तत्कालीन सरकारों के वित्त मंत्रियों ने बार-बार उस पर अपनी सफाई दी है और इसलिए उस प्रश्न के विस्तार में जाने की मैं समझता हूं कि आज के दिन कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन यह जरूर मैं कहना चाहूंगा कि सरकार की कोई नीयत नहीं है

कि हम उनके जो इनडिविजुअल डिसीजन्स हैं, उन इनडिविजुअल डिसीजन्स के ऊपर विचार करें।

नरेन्द्र मोहन जी जिन्होंने चर्चा की शुरूआत की, नहीं हैं, चले गए हैं, उन्होंने प्रश्न उठाया कि ईक्विटी क्यों बढ़ गई? 64 परसेंट क्यों पहुंच गई? अब इसमें, देखिए, समय-समय पर सरकारें फैसला करती हैं। एक 80 एम० का प्रावधान था जिसके तहत हम इस पर टैक्स में छूट देते थे। टैक्स में छूट जब वापस कर ली थी उस समय की सरकार ने तो उपसभाध्यक्ष महोदय, उस समय क्या हुआ? वह टैक्स की छूट जब हटा ली गई तो 1995 से लेकर 1997 तक तीन वर्षों में 18 हजार करोड़ रुपया लोगों ने रिडीम किया, वापस ले लिया यू०एस० 64 से क्योंकि जो एक बहुत बड़ी छूट थी, वह वापस हो गई लेकिन यू०टी०आई० क्या समाप्त हो गया 18 हजार करोड़ रुपया देने के बाद? यू०टी०आई० में इतनी ताकत थी कि उन 18 हजार करोड़ रुपए के रिडम्पशन के बावजूद यू०टी०आई० बना रहा और उसकी स्कीम्स चलती रहीं। यह 1994 से 1997 के बीच की बात मैं कर रहा हूं। यह सही है कि जब एक दफा इस बार ये नेगेटिव ऐसेट वैल्यू और इस तरह की चर्चा जब आई तो एक माहौल पैदा करने का प्रयास हुआ जैसे यू०टी०आई० बहुत संकट में है और मैं यह स्वीकार करता हूं कि मैंने कहा कि सरकार पूरी तरह से यू०टी०आई० के पीछे है। हम यू०टी०आई० को फेल नहीं होने देंगे और यह सही है कि मैंने कहा था कि जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फेल नहीं कर सकता है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फेल नहीं कर सकता है वैसे ही यू०टी०आई० भी फेल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा सबसे बड़ा बैंक है। इसलिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस देश का सैंट्रल बैंक है और यू०टी०आई० इस तरह है कि यू०टी०आई० आज हमारे पास सबसे बड़ा वह इंस्ट्रूमेंट है, हथियार है जिसके मार्फत, जिसके माध्यम से छोटे-छोटे निवेशकों को हम मौका देते हैं कि वह मार्किट में आएं और अपना पूंजी निवेश मार्किट में करें। इसलिए आज भी सरकार पूरी तरह से यू०टी०आई० के पीछे खड़ी है और यू०टी०आई० में अविश्वास का, यू०टी०आई० में विश्वास की कमी का, विश्वास के संकट का कोई प्रश्न इसलिए नहीं उठता है। मैं माननीय सदस्यों से भी निवेदन करुंगा कि जैसे हमारी कंसलटेटिव कमेटी है—जब इन सारे प्रश्नों को मैंने रखा था और सभी सदस्यों ने दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर कहा था कि हमें इसमें यू०टी०आई० के साथ हैं। सरकार के साथ नहीं है, इस देश के साथ है। राष्ट्रहित में हम सबको एक साथ खड़े होना है, आपको यह कहने में मुझे तनिक भी संकोच नहीं है। 21 हजार करोड़ रुपया अगर इसमें लगा हुआ है और उसके ऊपर किसी प्रकार का संकट पैदा हो जाए, यू०टी०आई० में अगर कोई संकट पैदा हो जाए तो इस देश के वित्तीय बाजार का क्या होगा? इसलिए यह सिर्फ वित्त मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ सरकार की जिम्मेदार नहीं है, हम सब यहां पर जितने माननीय सदस्य बैठे है, सबकी जिम्मेदारी है कि हम यह संकट न आने दें। विशेषकर उस परिस्थिति में जब यह संकट अकारण है। और हम जानते हैं के आज के युग में जहां पर हम चाहें न चाहें, हम विश्वीकरण से जुड़ गये हैं, हम ग्लोबलाइज्ड हो गये हैं। आज की परिस्थितियों में जहां हम देख रहे हैं कि दुनियां के दूसरे देशों में—हम तो 26 बिलियन डालर लेकर बैठे हैं, 29 बिलियन डालर हमारा टोटल रिजर्व है, जिनके पास 75 बिलियन डालर होता था, जिनके पास सौ बिलियन डालर होता था, वह आज धूल चाट रहे हैं क्योंकि जब भगदड़ मचती है तो ऐसी मचती है कि वह देशों को रौंदते हुए आगे बढ़ जाती है। जैसा हम सब जानते हैं। इसलिए उपसभाध्यक्ष महोदय, यह हमारा परम राष्ट्रीय कर्तव्य है कि हम इस तरह की भगदड़ होने से रोके और वह भी जब कि वह अकारण बन जाए। अगर उसका कोई कारण होता तो मैं खड़ा होकर यहां पर स्वीकार कर लेता कि यह कारण है। कल को हमारी स्टॉक मार्किट जो अभी किसी भी लैवल पर है, स्तर पर है, वह इम्प्रूव करेगी तो यह जो नोश्रल लॉस यू०टी०आई० का है, वह अपने आप पूरा हो जाएगा। इसलिए इसमें किसी प्रकार की घबराने की बात नहीं है किसी प्रकार का कोई स्कैंडल नहीं हुआ है, किसी प्रकार का कोई स्कैम नहीं हुआ है। मैं नहीं समझता हूं कि यह कोई ऐसा मौका है जिसमें हम संसदीय समिति गठित करके कहें कि इसमें जांच करो। अगर कभी भी हमारे मन में इस प्रकार की बात आएगी तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होउंगा जो इस सदन के समक्ष आकर कहेगा कि सभापति महोदय इसमें संसदीय समिति गठित करें और इसकी जांच पड़ताल कराएं। लेकिन मैं उसकी आवश्यकता इस वक्त महसूस नहीं कर रहा हूं। मैं सदन से निवेदन करुंगा कि हम सब मिलकर इस समय इसमें विश्वास व्यक्त करें। यू०टी०आई० में कुछ रिडम्पशन का प्रैशर बढ़ा था, कुछ दबाव बढ़ा था, लोग पैसा वापिस लेने लगे थे लेकिन मुझे कहने में संतोष हो रहा है कि इस साल जो हमने यू०एस०-64 में राशि हासिल की है, वह पिछले साल की तुलना में अधिक है। और मैं कहना चाहता हूं कि पिछले सप्ताहों के आंकड़े हमने देखे हैं। जो दबाव हमारे यू०टी०आई० के ऊपर था, लोग जो पैसा वापिस ले रहे थे उनका विश्वास लौट आया है और वह अब पैसा वापिस नहीं ले रहे हैं। हम बहुत ही

शुक्रगुजार है, हमारे मित्र, छोटे भाई राम गोपाल यादव जी ने मुझसे कहा कि उनका पैसा यू०एस०-64 में लगा हुआ है, वह उन्होंने वापिस नहीं लिया है। यह विश्वास उन्होने दिखाया है और मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर वह विश्वास दिखाना चाहिए ताकि यू०एस०-64 जिन प्रयोजनों को, जिस निमित्त के लिए बनाया गया था, उसके उन सिद्धांतों को, उन निमित्तों को, उन निदेशों को प्राप्त करने में हम सफल हो सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, I have just one question. The Hon. Minister has not replied to many of the questions. I am not going into those questions. But, I would like to know from him one thing. He finds UTI in fine colour; everywhere it is fine. May be. It may be nationally fine. I agree that the condition of the UTI is notionally fine. Anyway, I would like to know whether it is true that three successive audit reports, particularly the last one regarding the UTI, have raised serious doubts and qeustions about accounting, investment and UTI's management. Secondly, I would like to know whether it is true that in the corporate transactions I was referring to, the UTI has lost. There are many such instances. I have raised all these questions but he has not answered. Let him say that is it wrong with regard to audit reports. Let him say that what I am saying is wrong. He has not answered.

SHRI YASHWANT SINHA: I am waiting.

SHRI S. VIDUTHALAI (Tamil Nadu): The frequent changes of the Chairman has also been raised in this august House. External pressure is also exerted to get someone appointed as the Chairman in this institution. The appointment of the Chairman is criticised and this is also raised.

श्री यशवंत सिन्हा: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं पूरे विश्वास के साथ यह कहना चाहता हूं कि यू० टी० आई० के अध्यक्ष पद के लिए चयन में किसी प्रकार का कोई राजनीतिक दबाब नहीं था, न किसी प्रकार की कोई राजनीतिक भावना उसमें काम कर रहा था। सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जब हमने देखा हमारे कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पिछले महीनों में खाली हुए थे, उनकी शीर्षस्थ पर जो थे वह खाली हुए थे और अभी जो यहां पर कहा गया कि सब में एडहोकिजम है; मैं कहना चाहता हूं कि वहां के अध्यक्ष को अगर वहां से हटाया गया तो इसको आई० डी० बी० आई० का चेयरमैन बनाया गया जो कि शीर्षस्थ वित्तीय संस्था में माना जाता है। सारी बातों पर विचार करने के बाद और बिना एक मिनट भी लाए हुए हमने वहां पर कोई एडहोक ऐरेंजमेंट नहीं किया है। हमने वहां पर परमानेंटली एक व्यक्ति को अध्यक्ष पद जो सरकार का अधिकार है; वहां पर दिया है। इसलिए यह कहना कि एडहोकिजम चल रहा है अध्यक्ष पद में, यह सही नहीं है। जहां तक दूसरा प्रश्न है गुरूदास दासगुप्त का, आडिट रिपोर्ट के बारे में यह कहा गया कि वहां पर यह सारी लीक कर जाते हैं....(व्यवधान)

SHRI R.K. KUMAR: You can put questions and should I not? *(Interruptions)*. I want to say something on the audit report. *(Interruptions)* The most unfortunate part of the audit report is ...*(Interruptions)*... As a Member of this House I have my own opinion about this audit report, non-publication, comments, this or that. I am a Chartered Accountant. With due respect to my profession I would say that the tone, the tenor and the language of this report is not understandable, most of the time, even to any other professional leave alone the common man.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: The audit report is also national. Nothing is to be believed except the Finance Minister. Nobody is to be believed.

श्री यशवंश सिन्हा: उपसभाध्यक्ष महोदय, आडिट रिपोर्ट की यहां पर चर्चा की गई। उसी तरह इस बात की चर्चा की गई कि हमारे जो यू० टी० आई० के फैसले हैं वह लीक कर जाते हैं और उसका मार्केट के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन कई माननीय सदस्यों ने इस बात का उल्लेख किया लेकिन किसी ने भी कोई विशिष्ट जानकारी इसके बारे में नहीं दी कि इस समय लीक कर गए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आडिट के बारे में जो कि पब्लिश्ड है हर साल, जैसा हमने कहा कि सरकारी गजट में हम उसको पब्लिश करते हैं। अगर

कोई खास बात माननीय सदस्य गुरूदास दासगुप्त जी के ध्यान में तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उसको मेरे ध्यान में लाएं। उसमें कोई ऐसी बात होगी जिसमें सरकार को कार्रवाई करनी है, हम अवश्य ही उसमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक जनरल बात कर देना, एक सामान्य ढंग से बात करना कि ऐसा हुआ वैसा हुआ और इस सामान्य ढंग से बात करने में चर्चा यहीं समाप्त हो जाएगी, उसके बाद आगे उसमें कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है क्योंकि बात पूरी जनरल है।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, I have quoted the latest audit report. Categorically I have stated that the reserve is not enough to take care of the redemption. There is a serious depletion in the funds. *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): He has already stated about the terms. *(Interruptions)*

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: The minister is buying the argument of the management. *(Interruptions)*

SHRI YASHWANT SINHA: I have said it in my statement as to whait is the national loss. *(Interruptions)*

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: It is a notional loss! Any way, it is not a notional loss. The hon. Minister buys the argument of the management.

THE VICE-CHAIRMAN: Now we are concluding this. We will now take up the Government Motion.

GOVERNMENT MOTION

Thirtieth Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the Years 1989-91 Contd.

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): श्री ईश दत्त यादव। यादव जी आपका चार मिनट का समय बाकी है। आप बोलिए।

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, कल से जिस प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इस प्रस्ताव का संबंध इस देश की लगभग एक-चौथाई आबादी के लोगों से है। मैंने कल भी निवेदन किया था कि 50 वर्ष से संविधान में व्यवस्था होने के बाद भी, कानून बनने के बाद भी और सरकार द्वारा बजट आबंटित करने के बाद भी अनुसूचित जाति और जनजाति के भाईयों का अपेक्षित विकास नहीं हो सकता क्योंकि जिन लोगों को इसे लागू करना था, चरितार्थ करना था, अमल में लाना था, उनकी मानसिकता नहीं थी कि इस वर्ग के लोग आगे बढ़ सकें और समाज की मुख्यधारा में आ सकें। यह मेरी समझ में एक मुख्य कारण है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, दूसरा कारण यह है कि कुछ योजनार्थ चला देने से या कुछ नौकरियां दे देने से पूरे वर्ग का, इनकी पूरी जनसंख्या का, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का विकास संभव नहीं है, क्योंकि नौकरियां सीमित हैं, सबको नौकरियां नहीं दी जा सकती हैं।इस का अन्य कारण है स्थान नहीं है, शिक्षा नहीं है, योग्यता नहीं है। लेकिन सरकार ने कभी गम्भीरता से इन वर्गों के समग्र विकास की चिन्ता नहीं की, चाहे जो सरकार रही हो, वर्तमान सरकार हो या चाहे इसके पहले की सरकार रही हों। इनका समग्र विकास केवल दो माध्यमों से हो सकता है। इस वर्ग की जनसंख्या को योजनाओं और सुविधाओं के अतिरिक्त जमीन में भी हिस्सेदारी दी जाए। पूरे देश में भूमि सुधार कानून लागू नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश और बिहार को छोड़कर के और इसका नतीजा यह हुआ कि इस वर्ग के लोगों को लेबर का काम करना पड़ रहा है, मजदूरी का काम करना पड़ रहा है। हम अपने यहां की बात जानते हैं। हम पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार के बार्डर के पास से आते हैं। हमें पता है कि बिहार के लोगों को और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को देश के कोने-कोने में मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता है, कलकत्ता जाना पड़ता है, मुम्बई जाना पड़ता है, पंजाब जाना पड़ता है। पंजाब और हरियाणा के जो बड़े खेत वाले, जोत वाले लोग हैं, उनके खेतों में इनको मजदूर की हैसियत से काम करना पड़ता है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से श्रीमती मेनका गांधी जी को कहना चाहूंगा कि अब इनके विभाग का नाम सामाजिक न्याय हो गया है और अधिकार भी बढ़ गए हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि देश के अन्दर भूमि सुधार कानून को लागू किया जाए।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): आपका समय हो गया है।

श्री ईश दत्त यादव: अभी तो मेरी भूमिका.....